

राजस्थान सरकार

समेकित बाल विकास सेवाएं

2 जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।

एफ11(3)117/मो./मबावि/आईसीडीएस/2017-18 19888-121 जयपुर, दिनांक: 5/6/18

उपनिदेशक,


महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषय:-जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन हेतु नालसा द्वारा लागू की गई लीगल सर्विसेज कैम्प मोड्यूल के तहत शिविर आयोजित करने के क्रम में।

सन्दर्भ:-विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.स), विधि (ग्रुप-2) विभाग का पत्र क्रमांक प.8 (9) विधि-2/विरसं (74)/2015/793 दिनांक 18.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी पत्र मय लीगल सर्विसेज कैम्प मोड्यूल की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,

राजस्थान जयपुर

एफ11(3)117/मो./मबावि/आईसीडीएस/2017-18 19888-121 जयपुर, दिनांक: 5/6/18
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.स), विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को पालनार्थ।
3. ए.सी.पी मुख्यालय पर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

अति निदेशक (आई.)

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प 8(9) विधि-2/ विरसं (74)/2015/ 793 दिनांक : 13/05/18

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान।

PLR

23/5/18

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी-योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नालसा द्वारा लागू की गई लीगल सर्विसेज कैम्प मॉड्यूल के तहत शिविर आयोजित करने के क्रम में।

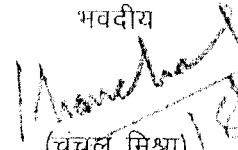
सन्दर्भ :- प्राधिकरण का पत्र क्रमांक एफ-7(83)नालसा/संस्था-वि.प्र./2017/37068 दिनांक 31.01.2018।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी पत्र एवं संदर्भित पत्र मय लीगल सर्विसेज कैम्प मॉड्यूल की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

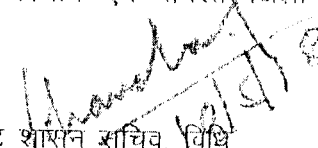
- संलग्न : 1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र क्रमांक 37068 दिनांक 31.01.2018 मय लीगल सर्विसेज कैम्प मॉड्यूल की प्रति।
2. मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.05.18 की प्रति।

भवदीय


(चंचल मिश्रा) 13/5/18

विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

प्रतिलिपि प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान एवं समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को ई-मेल करवाये जाने हेतु प्रेषित है।


विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक :- एफ-7(83)राजसा/संस्था-वि.प्र / 2017 / 37-068

दिनांक :- 31-01-2018

प्रेषिणी :-

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नालसा द्वारा लागू की गई लीगल सर्विसेज कैम्प मॉड्यूल के तहत शिविर आयोजित करने के संबंध में।
संदर्भ :- राज्य सरकार के अ.सा टीप क्रमांक :- एफ. 8(9)विधि-2/15/86 जयपुर, दिनांक 11.05.2015

Handwritten notes:
1 FEB 2018
SK (VRS)
12783/MS/18
1.2.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निवेदन पर भेजा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना माननीय मुख्य सचिव महोदय के संदर्भित आदेशानुसार प्रदेश में लागू की जा कर योजना की प्राप्ति जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों को भेजकर निर्देश दिये गए थे कि इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के क्रम में विधिक सेवा संस्थाओं के सहयोग प्रदान किया जावे, उक्त स्कीम को अभूतपूर्व सफलता, आमजन को राहत एवं लाभ मिला परंतु उक्त स्कीम राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 22.08.2016 से प्रत्याह्वन कर ली गई थी।

इस संबंध में अनुरोध है कि इन कैम्पस की रिपोर्ट्स का देखते हुये अन्ततः माननीय न्यायाधिपति महोदय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने नवीन विधिक सेवा कैम्पस मॉड्यूल को अनुमोदित कर ए.सा. टी.प. लागू करने हेतु आदेशित किया है।

माननीय न्यायाधिपति श्री के.एस. डवेरी, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश प्रदान किये है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कैम्पस मॉड्यूल यंत्रिकी, निर्माण व्यय, बालकों, ट्रांसजेन्डर्स, बन्धियों, एस.सी व एस.टी, बुद्धजनों, गिरीयार रहित व विध्याथियों को लक्ष्य व दुर्घटना, आपदाग्रस्तों आदि के हितार्थ कैम्पस आयोजन कर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूर्व की भांति जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों को इस पत्रकारि कैम्प योजना का सफलतापूर्वक बनाने के लिए राज्य सरकार स्तर पर आदेश प्रसारित करावे। इसके लिए अनुसंध पत्र श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः आपसे निदेशानुसार अनुरोध है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कैम्पस मॉड्यूल का प्रभावी क्रियान्वित करवाने हेतु निर्दिष्ट निर्देश यथाशीघ्र जारी करवाने सुनिश्चित करावे ताकि माननीय न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

कृपया इसे सर्वाच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय
(एस.के. जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।



“Legal Services CampModule”

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

12/11 JAM NAGAR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI

Website: www.nalsa.gov.in, E-mail: nalsa-dta@nic.in

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1	INTRODUCTION	1
2	STATUTORY MANDATE	1-2
3	OBJECTIVES OF LEGAL SERVICES CAMP	3
4	SUGGESTED THEMES/ ISSUES WHICH MAY BE COVERED IN A LEGAL SERVICES CAMP	3-5
5	<u>PRE-CAMP STEPS</u> 5.1 Identification of target population 5.2 Formation of team for connecting with the intended beneficiaries 5.3 Identification of specific welfare schemes and departments implementing them 5.4 NALSA Schemes 5.5 Holding of pre-camp preparatory meetings with stakeholders 5.6 Identification of venue for the camp 5.7 Field visits by outreach teams in the district/adjoining areas 5.8 Publicising the organisation of legal services camp 5.9 Identifying of presenters by participatory government departments/ministries during the camp. 5.10 Physical lay-out of the Camp	5-11
6	DURING CAMP	12
7	AFTER CAMP ACTIVITY	13
8	SOME OTHER IMPORTANT POINTS	14

the functions spelt out in Section 4(1)

"take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker section of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures"

This itself reflects that apart ensuring Access to lawyers and legal advice, the mandate of the Legal Services Authorities also extends to educate the weaker sections of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures.

In view of the Section 4(b) of the Legal Services Authorities Act, NALSA has promulgated the following schemes as strategic and preventive programmes and to educate the weaker sections of the society about their entitlements and empower them to get redressed their grievances in accordance with the law of the land.

One of the functions as per Section 4(e) of National Legal Services Authority is to organise Legal Aid Camps especially in rural areas, slums, labour colonies with the dual purpose of educating weaker sections of the

1. INTRODUCTION:

Access to justice is essential for rule of law. Access to justice, enable citizens to have their voices heard, exercise their rights and challenge discrimination. Access to Justice is not confined to court based legal services. It extends to making people aware about their entitlements under various enactments and welfare schemes and programmes and strengthening their access to the same. Some Legal Awareness Camps are being held by the State Legal Services Authorities to make people aware about their entitlements and apprise them about the availability of free legal services. In most of the camps, it has been observed, only creating of awareness is focussed on. There is a need to effect paradigm shift from awareness to empowerment. For this to happen, a new Model of holding Legal Services Camp is required which would not only make people aware about their entitlements and procedural aspects relating to the same but also connect them to the welfare schemes meant for them. Delivery based Model for holding Legal Services Camp is required.

2. STATUTORY MANDATE

Legal Services Authorities Act, 1987 was passed with an objective to provide free and competent legal services to weaker sections of the society so that they do not remain deprived of justice due to economic or other disabilities. This Act has created Legal Services Authorities primarily with an aim to provide legal services to weaker and marginalised sections of the society.

- Child Information provides the various functions of the Central Authority. One of
- Child Labour.
- Issues related to rights under Food Security Act.
- Establishment of Legal Literacy Clubs in Higher Secondary and Senior Secondary Schools.

4.4 Transgenders

- Ensuring benefits of welfare legislations/schemes. Issues dealt in NALSA vs. Union of India & Ors. (W.P.(C) No.400/2012).

4.5 Prisoners

- Ensuring representation before court.
- Availability of legal services for inmates.
- Digitisation of legal services clinics in jails.
- Adoption of E-Prison Portal by Jails.

4.6 Issues relating to SC/STs

- Ending discrimination.
- Partnering with State Commission of SC/ST on all issues pertaining to them.

4.7 Senior Citizens

- Ensuring benefits of welfare legislations/schemes.
- Availability of legal services including issues relating to Maintenance and Welfare of Parents & Senior Citizens Act, 2007.
- Senior Citizens Pension issues, if any.
- Elderly abuse, neglect and abandonment.

4.8 Beggars and homeless

- Exploring facilities available for them.
- Identifying abuse, trafficking etc.

4.9 Road Safety and accident

- Awareness about road safety signs.
- Protection to good Samaritans.

4.10 Victims of Disasters

- Problems/legal issues faced by people affected by drought/flood/industrial disasters. Short term and long term planning.
- Minimizing the impact of flood etc. A mechanism for drought stricken and sustenance to victim.

through Lok Adalats.

3. OBJECTIVES OF LEGAL SERVICES CAMP:

The Legal Services camp must aim to achieve the following objectives:-

- 3.1 To spread awareness about welfare legislations and schemes, and strengthen the community's access to the schemes being implemented by the Legal Services Authority and other departments of government.
- 3.2 Identifying and connecting people to welfare schemes to ensure that fruits of welfare schemes are passed to eligible people.
- 3.3 To understand legal needs of people and address legal problems of people by giving appropriate legal advice and taking other necessary steps.

4. SUGGESTED THEMES/ ISSUES WHICH MAY BE COVERED IN A LEGAL SERVICES CAMP

4.1 Labour

- Connecting unorganised sector workers to welfare schemes.
- Issues of construction / agricultural labour
- Availing benefit under Centre and State Schemes.
- Legal Services in any other issues relating to entitlements under labour laws.

4.2 Persons with disabilities

- Addressing disconnect between welfare schemes and persons with disabilities.
- Taking steps to connect beneficiaries with schemes such as Niramaya and Gyan Prabha run by National Trust.
- Ensuring legal services in any other issues.

4.3 Children related issues

- Addressing educational rights of children aged between 6-11.

them aware about the organisation of Legal Services Camp and to ensure that benefits arranged at the Camp reaches them.

5.3 Identification of specific welfare schemes and departments implementing them

Welfare Schemes and legislations pertaining to core theme be identified. Government departments related to the said core theme be identified. Departments who are even remotely related to the sections of people of core theme be also identified so that multi-dimensional and holistic approach is adopted to ensure access to justice in a meaningful and effective manner. For instance, if the core theme is rights of labourers then, regarding that core theme, the relevant departments/entities would be Department of Labour, Department of Social – Welfare, Department of Health, Department of Women and Child, Ministry of Skill Development, Common Services Centres. These said departments/entities would be the main Departments. Main focus of the camp shall be to connect people with the schemes being run by the main departments related to core theme. Apart from those main departments, other entities and departments which can provide benefit to labourers on the day of camp be also identified. In the given illustration, another department can be department of education to take care of the educational rights of children of labourers etc. Services at Common Services Centres may be availed.

efforts are made to benefit the marginalized sections of the society. They be apprised about the objectives of the legal services camp, pre-camp steps and activities during camp etc.

5.6 Identification of venue for the camp

Open Space be also identified where legal services camp can be held for identified villages. It should be kept in view that the space must be large enough to accommodate around 1500/2000 people and setting up of stalls, LED screen etc.

5.7 Field visits by outreach teams in the district/adjoining areas

Teams in association with NGOs, if any, shall make field visits to identify people related to the core theme. Field visits must start at least fifteen days prior to holding of camp. Teams must identify targeted people related to core them. They must also interact with those people to apprise them about the welfare schemes/programmes related to them. Teams shall disseminate information about camp such as its importance/objectives and relevance to their lives to let people know about the importance of camp. People be also told to bring necessary identity documents required for filling up forms related to schemes. Sarpanches/Panchayat members of the identified villages be also requested to come on the day of camp. They be also requested to mobilise people related to core theme of the camp. Presence of Sarpanches

5.10 Physical lay-out of the Camp

Camp's physical lay-out be also designed for the convenience of the villagers/participants. Separate registration stalls for males and females be put. Stalls for different departments including that of Legal Services Authority be also planned in coordination with the government departments. Two/three stalls be kept for NGOs and team members to fill up the forms for getting people connected with schemes. Arrangement for photocopier and adequate stationary be made in the said two/three stalls of the team members and NGOs. Power supply be also ensured to those stalls and LED. LED be placed at a place visible to participants. LED Screen is required so that the NALSA theme song and any other documentary relating to legal services authorities may be shown. The suggested camp design is as follows:

and Panchayat members is also required as while submitting forms identification of applicant is required to be made.

5.8 Publicising the organisation of legal services camp

Before holding camp, mobilization be also done through community meetings and by door-to-door visits of field teams to disseminate information about camp. Information about details of the camp through loud speakers and community radio be also disseminated. Adequate number of hoardings be also placed at public places to give information to public about the venue and date of legal services camp.

5.9 Identifying of presenters by participatory government departments/ministries during the camp.

Meetings with the Officers of the concerned departments be held to chalk out strategies for conducting Legal Services Camp on the core theme. They be apprised about the objectives of the camp, pre-camp steps etc. They be also requested to have adequate pamphlets, booklets, application forms etc. relating to welfare schemes/programmes of their departments in vernacular language on the day of camp. They be also requested to nominate presenting officers who will give very brief presentation about the welfare schemes to people on the day of camp in local language.

6. DURING CAMP

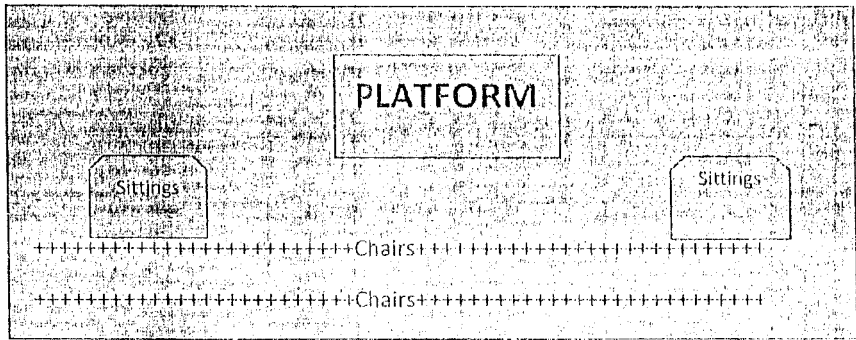
6.1 Short presentation by the Departments/Ministries

The main Departments relating to core theme shall give presentation in local language about the relevant welfare schemes of their Department. They shall briefly spell out the eligibility criteria under the Schemes. Each Department shall not take more than five minutes for the said purpose.

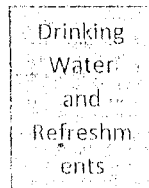
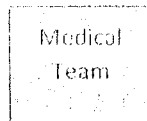
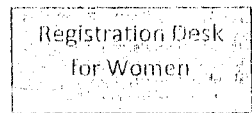
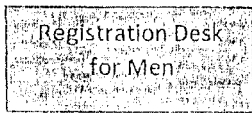
6.2 Real time registration of beneficiaries during the Camp.

After overview by Departments about various schemes, people shall be visiting the stalls of Departments including that of Legal Services Authority. The Officers of Departments at the stalls shall not only apprise people about the welfare schemes and distribute pamphlets regarding the same but shall also fill up the forms so that the same are processed further for getting people connected with the schemes.

6.3 For the purpose of filling up forms under different schemes, people may be referred to the stalls of NGOs/teams who shall fill up forms and attach necessary documents with the form. The teams/NGOs at the end of the programme shall submit the said forms to the different concerned departments.



Stalls of Legal services authority
Govt. Department/NGOs/teams



7. AFTER CAMP ACTIVITY

7.1 Preparation of Camp Report

A detailed report be prepared regarding the Legal Services Camp. It shall, inter-alia, spell out the activities done at the different stalls, application forms filled up with regard to different schemes etc. Lessons learnt from the camp also be clearly indicated so that improvements are made in upcoming camps to effectively reach out to people and getting them connected with the welfare schemes/legislations.

7.2 Follow up of all registrations done during the Camp.

Follow up action be taken on the various application forms submitted during the camp and the applications/representations written of the visitors relating to various issues.

7.3 Clearance of Camp Bills.

Bills of agencies whose services are taken for arranging the camp be cleared preferably within a week. Bills of Panel Advocates and PLVs associated in pre-camp activities and also during camp be also cleared within a week.

7.4 Maintenance of Cleanliness

Clearance of garbage etc. at the place where camp was held be also ensured.

8. SOME OTHER IMPORTANT POINTS

8.1 The duration of the camp shall be of 4-6 hours.

8.2 The time for opening Legal Services Camp be decided keeping in view weather condition and any other local conditions.

8.3 Adequate Drinking Water arrangements be made at the camp.

8.4 Refreshments including tea/biscuits be arranged for participants/villagers.

8.5 To deal with any emergency, Medical Team and Fire Fighting Team be also kept on standby.

8.6 Local police be also requested to put adequate number of policemen on duty at the camp site to avoid any chaos at the spot and to deal with any emergency.

8.7 Legal Services Camp should not be given the shape of a seminar, and hence, inaugural sessions speeches must be avoided. The focus should be to deliver by connecting people with the identified schemes and redress their problems.

8.8 Arrangements be also made for cord-less mics and standing mics.

8.9 Help Desks be also set up to help people during the camp by guiding them to the different stalls.

8.10 Adequate number of Registration Stalls be put up so that long queues are not formed and delay is avoided in registration of the participants

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.8(9)विधि-2/विरसं(74)/2015

जयपुर, दिनांक - 14/05/18

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान।

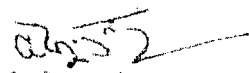
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:- विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नालसा द्वारा लागू की गई लीगल सर्विसेज कैंप मॉड्यूल के तहत शिविर आयोजित करने के क्रम में।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा श्रमिकों, निर्वाग्य व्यक्तियों, बालकों, ट्रांसजेन्डर्स, बन्धियों, एरासी व एमटी, वृद्धजनों, निवारण रक्षित व भिखारियों, रोड़ सुरक्षा व दुर्घटना, आपदाग्रस्तों आदि के हितार्थ विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर आमजन को सहत पहुँचाने के लिए "लीगल सर्विसेज कैंप मॉड्यूल" बनाया गया है। उक्त मॉड्यूल में शिविर आयोजन की योजना विस्तार से बताई गई है जो निश्चित रूप से समाज उपयोगी है एवं अपने अर्थ में विस्तृत व स्पष्ट है। नालसा के "लीगल सर्विसेज कैंप मॉड्यूल" के तहत विधिक सेवा शिविर आयोजित करने में प्रशासन व सम्बन्धित विभागों का सहयोग व समन्वय अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लीगल सर्विसेज कैंप मॉड्यूल की प्रति सभी जिला कलेक्टर एवं सम्बन्धित विभागों को भेजकर निर्देश है कि इसकी सफलता सुनिश्चित करने के क्रम में विधिक सेवा संस्थाओं को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव